amounts of reductions have had to be made, but I hope that we will be able, by and large, to stick to the programme.

Shri Sinhasan Singh: The barrage in Gandak project is divided into two parts: the barrage in Bihar section, along with canals, under the Bihar Government and the other part of the canal section in the U.P. May I know whether this amount of Rs. 121 crores covers both the barrage and the canal under both the States and what was the original target date for completion and what is the revised target date for the completion of this, after having revised the estimate to Rs. 121 crores?

Dr. K. L. Rao: There are actually three canals: two on the eastern side and one on the western side. Some portion of the length of the one which is on the western side passes through U.P. territory. Rs. 121 crores consist of the estimates of both the Bihar area and the U.P. area. The cost of the portion relating to U.P. comes to Rs. 26 crores out of the total of Rs. 121 crores.

श्री विभूति मिश्र : मेरे प्रश्न का जवाब इन्होंने नहीं दिया है, मैंने पूछा था रमैया कम्पनी के बारे में। इन्होंने कह दिया कि गवर्नर उसके चेयरमैन हैं, लेकिन वहां पर काम नहीं हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि काम हो रहा है।

सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का दिया जाना

+

***1104. श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उपयुक्त आवास उपलब्ध न होने के कारण, जिसके वे हकदार हैं, उच्चतर वर्गों के कर्मचारियों को ऐसे क्वार्टर दिये जाते हैं जो उनसे नीचे के वर्ग के कर्मचारियों के लिए बने होते हैं और यथा समय बारी आने पर भी उन्हें वे क्वार्टर नहीं दिये जाते जिनके वे हकदार होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि नीचे के वर्गों के कर्मचारियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दस-दस साल तक भी उन्हें उपयुक्त आवास नहीं मिल पाता; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) केवल टाईप VII और VIII के हकदार अफसरों को जब उनकी केटेगरी का मकान खाली नहीं होता तब उन्हें एक कैटेगरी नीचे का मकान अलाट कर दिया जाता है। टाईप VI और उससे नीचे के हकदार अफसरों को अब एक कैटेगरी नीचे का मकान अलाट नहीं किया जाता। जब ऐसे अफसरों की बारी आती है तो जिस टाईप के वे हकदार होते हैं उसी टाईप में उन्हें अलाट कर दिया जाता है।

(ख) टाईप VII और VIII के हकदार अफसरों को एक कैटेगरी नीचे का अलाटमेंट देने से निचले कैटेगरी के हकदार अफसरों के हक पर कोई असर नहीं पड़ता।

(ग) मकानों के अलॉटमेंट की हालत कोई अच्छी नहीं है। लगभग एक लाख

मकानों की मांग की जगह पर हमारे पास सिर्फ 39,000 मकान अलाटमेंट के लिए हैं। इस समस्या का हल एक ही है कि ज्यादा मकान बनाये जायें लेकिन बचत की वजह से हमारा इमारतों का काम बिल्कुल कम कर दिया गया है।

श्री भागवत झा आजाद: माननीय मंत्री जी ने बताया है कि अगर क्वार्टर्स उसी क्लास के अवेलेबिल नहीं होते हैं तो नीचे वाली क्लास के दे दिये जाते हैं, ऐसी स्थिति में उनके हक पर असर नहीं पड़ता है। क्या उनकी कठिनाइयां नहीं बढ़ती हैं, अगर यह बात सही है तो नीचे दर्जे के व्यक्तियों को भी इसी तरह से दिया जाय?

Shri Bhagavati: As I have stated already, now that system has been changed. Only so far as types VII and VIII are concerned, the officers entitled are allowed the next-below type of accommodation, and the rest are not allowed the next-below type of accommodation. So, the junior officers are not at all affected by this.

श्री भागवत झा आजाद: मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान असेसमेन्ट, गणना के अनुसार हमारे पास जितने क्वार्टर्स की आवश्यकता है, उसकी तुलना में कमी कितनी है और कितनों को मिलने की सम्भावना है?

Shri Bhagavati: I have already indicated the number. The total demand throughout the country is 1,48,401, and the availability is only 42,631. So, the shortage is 1,05,770.

Shri Bhagwat Jha Azad: What is the achievement of Government?

Shri Bhagavati: The position is not good.

Shri Subodh Hansda: What is the length of service of the senior officers who have already got the allotment and what is the length of service of the junior officers who have not got the allotment?

Shri Bhagavati: So far as the senior officers are concerned, their number naturaly is much smaller. For Type VII, the demand is only for 246, and that for type VIII is only for 108. The satisfaction in these types is 70 per cent and 61 per cent, whereas in the lower types, that is types I, II and III, the satisfaction will be 46 per cent, 30 per cent, 32 per cent and so on; the position in the lower types certainly is not satisfactory.

Shri S. C. Samanta: May I know whether complaints have been received by the Ministry that houses have not been allotted to those employees who are serving for more than ten years whereas people of the same category who have served for less than ten years have been allotted houses, and if so, in how many cases, and how the complaints have been dealt with?

Shri Bhagavati: I donot think that any discrimination is made. A definite policy is pursued. So far as types I to V are concerned, that is, so far as the junior officers are concerned, their date of appointment is taken into consideration as the priority date. For the other types, the date of confirmation to the higher post or promotion to that category is taken into consideration as the priority date; according to the priority date, the houses are allotted. No discrimination is made.

Shri S. C. Samanta: I wanted to know whether the rules had been observed.

श्री हुकम चन्द कछवाय: जो कर्मचारी स्थानान्तरित होकर दिल्ली आते हैं, उन्हें मकान मिलने में काफी कठिनाई होती है, क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि उनके स्थानान्तरित होकर आने के पहले

ही उनको क्वार्टर एलाट करके उनको पहले से सूचना दे देवे, तब वे अपने परिवार को दिल्ली लावें ?

Shri Bhagavati: The basic problem is acute shortage of houses in Delhi. During this year, we have no money for constructing new houses, because there is a cent per cent cut. So, the position is really not good. So far as it is possible to make allotment to the officers concerned, we have certain policies and we follow them scrupulously.

श्री ओंकार लाल बेरवा : बड़े अफसर जब छोटे मकानों में रहते हैं और उनका किराया देते हैं तो सरकार को किराये में नुकसान होता है । बड़े अफसरों को जो किराये में फायदा छोटे क्वार्टर देकर पहुंचाया जाता है, इसके बारे में भी क्या सरकार ने विचार किया है ? क्या इसके बारे में विचार किया है कि उनसे क्या किराया चार्ज किया जाय ?

Shri Bhagavati: That is not correct; if an officer who is given a higher type of accommodation but he occupies a type of accommodation below his entitlement, he is charged for the higher type of accommodation.

Shri Joachim Alva: Do Government make enquiries of officers who possess no cars and who have no chance of possessing cars so that they are given preference in allotment nearer the Secretariat? Also what about the class III and class IV employees who are living 20 miles away and who have no Government accommodation? Is there any long-term arrangement for their quarters?

Shri Bhagavati: It depends upon the availability of accommodation.

श्री यशपाल सिंह : सरकार की नीति पापुलेशन को कम करने की है । हालांकि हमारे धर्मशास्त्रों में इसको सब से बड़ा पाप लिखा हुआ है । लेकिन उसको आप छोड़ दें । सरकार पापुलेशन कम करना चाहती है । और इंजैक्शन से ले कर लूप तक सब तरीके फेल हो चुके हैं । ऐसी सूरत में सरकार यह नियम क्यों नहीं बना देती है कि सिर्फ अनमैरिड कर्मचारियों को क्वार्टर एलाट किये जायें और जो मैरीड लोग हैं वे सड़कों पर फिरते रहें? इससे आबादी बढ़ेगी नहीं । क्यों नहीं अनमैरिड लोगों को प्रफेंस दिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री लिमये ।

श्री मधु लिमये : जब पुराने सरकारी मकान किसी कारण तोड़ दिये जाते हैं तो क्या यह नियम है कि वहां रहने वाले जो कर्मचारी हैं उनको कोई अलग जगह दी जाए? यदि हां तो मैं जानना चाहता हूं कि डाक तार विभाग से कोई शिकायतें प्राप्त हुई है कि दिल्ली में रहने वाले ऐसे कर्मचारियों को जब उनके मकान तोड़ दिये गये तो कोई नए मकान नहीं दिये गये, यदि हां तो ऐसी शिकायतों के बारे में क्या किया जा रहा है ?

निर्माण, आवास तथा भगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): जहां तक वर्क्स हाउसिंग मंत्रालय का ताल्लुक है अगर हम किसी एलीजीवल एलाटी का मकान तोड़ते हैं तो हम उसको जरूर जगह देते हैं। जहां तक डाक और डाकखाने का ताल्लुक है, यह मेरा काम नहीं है । उनका पूल अलहदा है, उनका मंत्रालय अलहदा है ।

Shri S. M. Banerjee: Is it a fact that there were certain Government orders giving preference to women employees of Government in the matter of allotment of quarters which have recently been withdrawn? I would like to know whether such an order exists and, if so, whether any preference is given to ladies working in Government

Shri Bhagavati: There is a ladies' pool from which they are allotted quarters.

श्री काशीराम गुप्त : तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को क्या यह अधिकार दिया गया है कि उनके जो फ्लैट हैं उनका कुछ हिस्सा वे अपने साथी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दे सकते हैं, यदि हां तो क्या उसके किराये के ऊपर भी कोई प्रतिबन्ध है ?

Shri Bhagavati: I could not follow the question.

Shri Kashi Ram Gupta: Have Government allowed the class III and class IV employees to sublet their accommodation to the same categories of employees? If so, is the subletting to be done under certain rules and regulations or without these?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): As we are very short of accommodation, we are actually conniving at sharing by Government officers. The only condition we have laid down is that if any sharing is to be done, it should be between the allottee and an eligible officer, not an outsider.

Conference of Chairmen of Electricity Boards

*1105. **Shri Shree Narayan Das:**
Shri Krishnapal Singh:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the conclusions arrived at and the recommendations made by the Conference of Chairmen of State Electricity Boards held in November, 1965 so far as they concern the Central Government, have been considered; and

(b) if so, the decisions taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-6038/66].

Shri Shree Narayan Das: From the statement, it appears that final action with regard to setting up of rural electric cooperatives will be taken after discussions held with the experts of the U.S. National Rural Electric Co-operative Administration. How many experts have been invited and what will be the expenditure involved when they come here?

Dr. K. L. Rao: Two experts were invited and we are expecting them any time. The only expenditure involved is the actual costs here during their stay, whatever we spend by way of rupees here.

Shri Shree Narayan Das: In the statement it is said that the question of grant of five-year interest-free loan for rural electrification is being examined by the various Ministries concerned. I would like to know when a decision is likely to be taken, and whether any of the States have made any demands for this purpose, and if so, what is the demand?

Dr. K. L. Rao: Actually, all the States have made this demand and it has been under discussion with the Ministry of Finance. It will take some time.

Shri Krishnapal Singh: I believe that one of the points discussed at this conference was whether in the rural areas minimum charges for supplying electricity should be levied or not? The cultivators do not consume any electricity during the rainy season for four to five months in the year. Besides, they are charged rather high line rental charges for connecting the main lines to the distribution line. I wonder what decision has been taken by Government on these points.